

Daily Current Affairs

Date : 21 April, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम (CTSSS) में राजस्थान
2.	राजस्थान AI-ML पॉलिसी - 2026
3.	राजस्थान में 'Bt कपास' हाइब्रिड बीजों की बिक्री
4.	राजस्थान में जनगणना - 2027 का प्रथम चरण
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. स्वदेशी रक्षा आधुनिकीकरण के लिए भारतीय सेना और BITS, पिलानी के मध्य MoU 2. डॉ. संदीप बक्शी : UN IIMSAM के गुडविल एम्बेसडर
6.	भारत समुद्री बीमा पूल
7.	पेट्रोग्लिफ्स (शिलाचित्र)
8.	जगद्गुरु बसवेश्वर
9.	स्वर्ण खनन
10.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III)
11.	विश्व सूत्र
12.	समुद्र मंथन मिशन (नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन)
13.	बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)
14.	लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक विनिमय (RELOS) समझौता
15.	भारत-श्रीलंका संबंध: भारत के उपराष्ट्रपति की यात्रा
16.	भारत की पहली 'एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट'

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम (CTSSS) में राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (CCRT) द्वारा 'कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम (CTSSS)' के तहत छात्रवृत्ति की घोषणा की गई, जिसमें राजस्थान के 10 बाल कलाकारों का चयन किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप (CTSS) केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत CCRT द्वारा 10-14 वर्ष के प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रदान की जाती है।
- श्रेणियाँ** : नृत्य, संगीत, चित्रकला और नाटक आदि।
- छात्रवृत्ति के तहत प्रति वर्ष ₹3,600 छात्रवृत्ति और ₹9,000 तक ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) मिलती है, जो 20 वर्ष की आयु तक नवीनीकृत हो सकती है।

--2--

Daily Current Affairs

Date : 21 April, 2026



राजस्थान से चयनित कलाकार :

नाम	विषय
गीतिशा पांडे	नाटक
औनिक जैन	एच.एम. - वोकल
रजत पांडे	एच.एम.आई. - तबला
अन्वी जैन	कथक नृत्य
वेरोनिका पाहवा	कथक नृत्य
अन्निका गुप्ता	कथक नृत्य
निर्वी अजमेरा	कथक नृत्य
त्रिंजल राजावत	पेंटिंग
अथर्व बीजावत	पेंटिंग
यशस्वी इंदा	पेंटिंग

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र (CCRT) का राजस्थान में क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में स्थित है।
- यह केंद्र राजस्थान की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और शिक्षा के साथ उनके एकीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

--3--

राजस्थान AI-ML पॉलिसी - 2026

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान में शासन, शिक्षा, उद्योग और स्टार्टअप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) को बढ़ावा देकर राज्य को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने के उद्देश्य से 'राजस्थान AI-ML पॉलिसी - 2026' लागू की गई है।

**RAJASTHAN LAUNCHES
AI-ML POLICY 2026**

Governance • Public Services • Startups • Skills • Data Centres

AI Governance

E-governance

Healthcare

Smart traffic

STARTUP

FOUNDER

Building AI-Ready Governance.

---4---

Daily Current Affairs

Date : 21 April, 2026



मुख्य बिन्दु:

- **लॉन्च** : मुख्यमंत्री द्वारा 06 जनवरी, 2026 को जयपुर में 'राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस - 2026' के दौरान।
- **पूरा नाम** : राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड मशीन लर्निंग (AI-ML) पॉलिसी - 2026
- **घोषणा** : इस नीति की घोषणा राजस्थान बजट 2025-26 में की गई थी।
- **अनुमोदन** : राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा 30 दिसंबर, 2025 को अनुमोदन किया गया।
- **उद्देश्य** : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना तथा नवाचार-आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- साथ ही, राजस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (ITES) के हब के रूप में विकसित करना इस नीति के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल है।
- यह पॉलिसी सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्त्व को ध्यान में रखते हुए ई-गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करेगी।

--5--

Daily Current Affairs

Date : 21 April, 2026



- **प्रावधान :** इस नीति के अंतर्गत AI सिस्टम्स पारदर्शी, जवाबदेह, निष्पक्ष, गोपनीयता-संरक्षित बनाने के साथ-साथ AI प्रणालियों में पक्षपात को कम करने, डेटा की सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता पर विशेष बल दिया गया है।
- नीति में AI से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान हेतु स्पष्ट प्रक्रियाओं का प्रावधान भी किया गया है।
- इस नीति में स्कूलों, ITIs, पॉलिटेक्निक संस्थानों और कॉलेजों में AI शिक्षा को प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है।
- **नोट :** नीति में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना किए जाने का प्रावधान है।
- नीति के तहत प्रत्येक विभाग अपने-अपने कार्यक्षेत्र में AI उपयोग की संभावनाओं की पहचान करेगा तथा एक AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

--6--

राजस्थान में 'Bt कपास' हाइब्रिड बीजों की बिक्री

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राज्य सरकार द्वारा गैर-संशोधित (BG- II, GFM) बीटी कपास हाइब्रिड की व्यावसायिक खेती के लिए Bt कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री को औपचारिक अनुमति जारी की गई।

Bt cotton is currently the only GM crop approved for commercial cultivation in India.

Safe. Scientific. Sustainable.

- SAFE**
Rigorous scientific testing ensures safety for people, animals, and the environment.
- SCIENTIFIC**
Developed using advanced biotechnology to protect against bollworm.
- SUSTAINABLE**
Helps improve yield, reduce insecticide use, and support farmers' livelihoods.

Only GM Crop Approved in India

Bt COTTON
TRUSTED BY MILLIONS OF FARMERS

Bt Cotton – The only GM crop Approved. Trusted. Transforming Indian Agriculture.

Source: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

मुख्य बिन्दु:

- यह अनुमति केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) तथा Bt कपास पर स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है।
- सीजन :** खरीफ- 2026 के लिए।

Daily Current Affairs

Date : 21 April, 2026



- इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुमोदित 34 बीज कंपनियाँ राज्य के विभिन्न कृषि- जलवायु क्षेत्रों में निर्धारित शर्तों के अनुसार Bt कपास हाइब्रिड बीजों की आपूर्ति कर सकेंगी।
- **नोट :** श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे पश्चिमी जिलों में सफेद मक्खी (Whitefly) और कॉटन लीफ कर्ल वायरस (CLCuD) के प्रति संवेदनशील Bt कपास हाइब्रिड की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रखा गया है।

Bt कपास :

- Bt कपास, कपास की एक आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) कीट-प्रतिरोधी किस्म है। वर्तमान में, यह भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र GM फसल है।
- वर्ष 2002 में स्वीकृत यह भारत के 90 प्रतिशत से अधिक कपास क्षेत्र को कवर करती है, जिसका उद्देश्य बैसिलस थुरिंगिएन्सिस प्रोटीन के माध्यम से बॉलवर्म कीटों से लड़ना है

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)

- GEAC भारत की सर्वोच्च जैव प्रौद्योगिकी नियामक संस्था है।
- **मंत्रालय :** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अधीन।
- **स्थापना का आधार :** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित '1989 के नियमों' के अंतर्गत।
- **संरचना :** अध्यक्षता मंत्रालय के विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) का एक प्रतिनिधि सह-अध्यक्ष।

--8--

Daily Current Affairs

Date : 21 April, 2026



मुख्य कार्य:

- **GM फसलों को स्वीकृति** : भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (Genetically Modified) फसलों (जैसे - Bt कपास, GM सरसों) के व्यावसायिक उपयोग या पर्यावरणीय रिलीज के लिए GEAC की मंजूरी अनिवार्य है।
- **नियामक भूमिका** : यह खतरनाक सूक्ष्मजीवों, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) और कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण को नियंत्रित करती है।
- साथ ही, GEAC अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले पुनर्संयोजकों के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन भी करती है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--9--

राजस्थान में जनगणना - 2027 का प्रथम चरण

चर्चा में क्यों?

- 16 मई से 14 जून, 2026 के मध्य राजस्थान में जनगणना - 2027 के प्रथम चरण अर्थात् मकान सूचीकरण का कार्य सम्पन्न किया जाएगा।



मुख्य बिन्दु:

- जनगणना के प्रथम चरण "मकानसूचीकरण और मकानों की गणना (HLO)" को पूर्णतः डिजिटल और सहभागी बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) की सुविधा प्रदान की गई है।

स्व-गणना की अवधि : 1 से 15 मई, 2026 तक।

- स्व-गणना सुविधा का उद्देश्य कार्यरत, व्यस्त अथवा सुविधा अनुसार स्वयं विवरण उपलब्ध कराने के इच्छुक परिवारों को डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी भरने का अवसर प्रदान करना है।
- ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा 29 जनवरी, 2026 को जनगणना के प्रथम चरण में पूछे जाने वाले प्रश्नों (कुल 33) की अधिसूचना जारी की गई थी।
- जनगणना के आधिकारिक शुभंकर :** प्रगति (महिला) और विकास (पुरुष) हैं, जिनका अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री ने 5 मार्च, 2026 को किया था।
- जनगणना का ब्रांड एंबेसडर :** प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट और पद्म श्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक (ओडिशा)।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

जनगणना - 2027:

- भारत की 16वीं जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी, इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में अप्रैल, 2026 से सितम्बर, 2026 के मध्य मकानों के सूचीकरण तथा मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा।
- द्वितीय चरण में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि देश के बर्फीले क्षेत्रों में सितम्बर-अक्टूबर-2026 में तथा शेष सम्पूर्ण भारत में फरवरी-मार्च, 2027 में जनसंख्या की गणना होगी।

Daily Current Affairs

Date : 21 April, 2026



- भारत में जनगणना का कार्य केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा करवाया जाता है वहीं राजस्थान में जनगणना का उत्तरदायित्व सांख्यिकी विभाग का है।
- जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा - 3 के तहत एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार जनगणना से पहले मकान-सूचीकरण और आवास सर्वेक्षण की शुरुआत हुई है।
- पूर्णरूप से डिजिटल : वर्ष 2027 की जनगणना भारत में पहली पूर्णरूप से डिजिटल जनगणना होगी।
- जातिगत जनगणना : वर्ष 1931 के बाद पहली राष्ट्रव्यापी जाति-आधारित गणना होगी।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:12:-

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>स्वदेशी रक्षा आधुनिकीकरण के लिए भारतीय सेना और BITS, पिलानी के मध्य MoU</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS), पिलानी के मध्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।यह समझौता जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड मुख्यालय में सम्पन्न हुआ।इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य उभरती सैन्य परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप अकादमिक विशेषज्ञता को एकीकृत करना तथा आधुनिक युद्धक्षेत्र की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार-प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
2.	<p>डॉ. संदीप बक्शी : UN IIMSAM के गुडविल एम्बेसडर</p> <ul style="list-style-type: none">जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी (JNU) के चांसलर डॉ. संदीप बक्शी को हाल ही में UN IIMSAM (कुपोषण के विरुद्ध माइक्रो-एल्गी स्पाइरुलिना के उपयोग के लिए अंतर-सरकारी संस्थान) का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया।डॉ. बक्शी भारत के पहले ऐसे विश्वविद्यालय प्रमुख हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिष्ठित जिम्मेदारी मिली है।उनकी नियुक्ति वैश्विक स्तर पर कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाने और 'स्पाइरुलिना' (Spirulina) के पोषण संबंधी लाभों को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

राष्ट्रीय परिदृश्य

भारत समुद्री बीमा पूल

चर्चा में क्यों?

- सरकार ने जहाजों से वस्तुओं की आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए ₹12,980 करोड़ के भारत समुद्री बीमा पूल (Bharat Maritime Insurance Pool) को मंजूरी दी है। यह मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुरूप है।

मुख्य बिन्दु:

भारत समुद्री बीमा पूल

- उद्देश्य:** युद्ध या संघर्ष के समय विदेशी बीमा कंपनियों के हटने पर भी किफायती और निरंतर बीमा सुविधा सुनिश्चित करना।
- कवरेज:** हल (Hull), मशीनरी, कार्गो, संरक्षण और क्षतिपूर्ति (P&I) और युद्ध सहित सभी समुद्री जोखिम।
- महत्त्व:** यह व्यापार सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।

इतिहास एवं संस्कृति

पेट्रोग्लिप्स (शिलाचित्र)

चर्चा में क्यों?

- लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण उद्यान की आधारशिला रखी गई।
- इस उद्यान का उद्देश्य सदियों पुरानी चट्टानों की नक्काशी (पेट्रोग्लिप्स) के लिए एक विशिष्ट संरक्षण स्थल के रूप में कार्य करना है। ये नक्काशी अनियंत्रित पर्यटन, बुनियादी ढांचे के अधिक विकास और जागरूकता की कमी के कारण खतरे में हैं।

मुख्य बिन्दु:

पेट्रोग्लिप्स

- पेट्रोग्लिप्स प्रागैतिहासिक चित्र, प्रतीक या नक्काशी हैं। इन्हें सीधे शैलों की सतहों पर उकेरा जाता है।
- ये "मुक्त आकाश संग्रहालय" और "पत्थर पर खुदी हुई सभ्यताएं" हैं। ये पुरापाषाण काल से लेकर बाद के ऐतिहासिक काल तक के मानव इतिहास का निरंतर अभिलेख प्रस्तुत करते हैं।
- ये नक्काशी प्राचीन व्यापार मार्गों, प्रवासन पैटर्न और मान्यताओं को दर्शाती हैं। साथ ही, ये पारिस्थितिक इतिहास का भी वर्णन करती हैं।
- **भारत में प्रमुख पेट्रोग्लिप्स:** भीमबेटका (मध्य प्रदेश), रत्नागिरी (महाराष्ट्र), गाविलगढ़ पहाड़ियाँ (ओडिशा), आदि।

जगद्गुरु बसवेश्वर

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसव जयंती के अवसर पर जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
- बसवेश्वर, जिन्हें बसवन्ना के नाम से भी जाना जाता है, 12वीं शताब्दी के दार्शनिक, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे, जो मुख्य रूप से वर्तमान कर्नाटक के कल्याणा क्षेत्र में सक्रिय थे।
- उन्हें लिंगायतवाद का संस्थापक माना जाता है और उन्होंने समानता, सामाजिक न्याय और जातिगत पदानुक्रम तथा सामाजिक भेदभाव के खंडन की वकालत की।
 - लिंगायतों को "वीरशैव लिंगायत" नामक एक हिंदू उपजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें शैव माना जाता है।
- उन्होंने कलचुरी वंश के राजा बिज्जल द्वितीय के अधीन मंत्री के रूप में कार्य किया।
- बसवेश्वर ने इष्टलिंग की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो सामाजिक विभाजनों से परे जाकर ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संबंध को बढ़ावा देती है।
- उन्होंने अनुभव मंडप (जिसे अक्सर दुनिया की पहली संसद कहा जाता है) की भी स्थापना की, जो खुले संवाद के लिए एक अग्रणी मंच था, जहाँ महिलाओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग आध्यात्मिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा में भाग ले सकते थे।



भूगोल एवं भू-विज्ञान



स्वर्ण खनन

चर्चा में क्यों?

- भारत में निजी क्षेत्र की पहली स्वर्ण खनन परियोजना आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले (जोन्नागिरी खदान) में शुरू होने वाली है।

मुख्य बिन्दु:

स्वर्ण

- स्वर्ण एक नरम, लचीली और संक्षारण प्रतिरोधी धातु है। यह धातु प्राकृतिक रूप में (नगेट्स, दरारों की सुनहरी नसों, जलोढ़ निक्षेपों) पाई जाती है।
- यह साइनाइड (खनन में प्रयुक्त) में घुल जाता है और पारे के साथ अमलगम बनाता है।

निक्षेप और वितरण:

- **भारत:** 518.23 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क (2020 तक)।
- **शीर्ष राज्य (निक्षेप):** बिहार (43%), राजस्थान (लगभग 25%) और कर्नाटक (लगभग 20%)।
- **उत्पादन में अग्रणी:** कर्नाटक (लगभग 97%); मुख्य खदान हट्टी स्वर्ण खान है।
- **प्लेसर निक्षेप:** केरल।

विश्व:

- **शीर्ष उत्पादक:** चीन (10%), रूस, ऑस्ट्रेलिया।
- **शीर्ष आयातक:** स्विट्जरलैंड, चीन, ब्रिटेन।
- **शीर्ष निर्यातक:** स्विट्जरलैंड, UAE, ब्रिटेन।

योजनाएँ एवं नीतियाँ

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III) को मार्च, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

मुख्य बिन्दु:

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की मुख्य विशेषताएँ:

- **शुरुआत:** 25 दिसंबर, 2000 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में।
- **उद्देश्य:** असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़कर निर्धनता कम करना। इसके लिए जनसंख्या मानक इस प्रकार हैं:
 - मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक की आबादी वाली ग्रामीण बस्ती।
 - विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जैसे पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य, रेगिस्तानी क्षेत्र और चुनिंदा पिछड़े जिले) में 250 या उससे अधिक की आबादी।
- **योजना के प्रमुख चरण:**
 - **PMGSY-चरण I (2000):** पात्र असंबद्ध (सड़क से नहीं जुड़ी) बस्तियों को प्रारंभिक बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
 - **PMGSY-चरण II (2013):** इस चरण में ध्यान नई सड़कें बनाने से हटाकर मौजूदा ग्रामीण सड़कों के सुधार पर दिया गया। इसका लक्ष्य 50,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाना था।

Daily Current Affairs

Date : 21 April, 2026



- o वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण (2016): वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित नौ राज्यों के 44 जिलों को लक्षित किया गया।
- o PMGSY-चरण III (2019): गांवों को सीधे ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने के लिए 1,25,000 किलोमीटर के मुख्य मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों में सुधार का लक्ष्य रखा गया।
- विस्तार: इस चरण को अब मार्च, 2025 से बढ़ाकर मार्च, 2028 तक कर दिया गया है।
- PMGSY-चरण IV (2024-25 से 2028-29): पूर्व में असंबद्ध 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त 62,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:19:--

विश्व सूत्र

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने 'विश्व सूत्र -विश्व के लिए भारत के बुनकर' नामक एक पहल शुरू की है।

मुख्य बिन्दु:

विश्व सूत्र

- यह पहल राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा शुरू की गई है।
- **उद्देश्य:** भारतीय हथकरघा को समकालीन वैश्विक डिजाइन ढांचे में प्रस्तुत करना।
- इसके तहत देश भर से 30 अलग-अलग हथकरघा बुनाइयों को एक साथ लाया गया है। इनमें से प्रत्येक बुनाई एक अलग राज्य का प्रतिनिधित्व करती है।
 - इन बुनाइयों को 30 देशों से ली गई डिजाइन प्रेरणाओं के साथ रचनात्मक रूप से पुनर्व्याख्यायित किया गया है। ये विविध सांस्कृतिक तत्वों, सिल्हूट और डिजाइन संवेदनाओं को दर्शाती हैं।
 - **उदाहरण:** ग्रीक रूपों के साथ ओडिशा इकत, नॉर्वेजियन रेखाओं के साथ कांचीपुरम, मिस्र के तत्वों के साथ मूंगा, स्पेनिश प्रभावों के साथ पटोला और (UAE) से प्रेरित पहनावे के साथ बनारसी।

समुद्र मंथन मिशन (नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन)

चर्चा में क्यों?

- समुद्र मंथन मिशन गहरे जल में अन्वेषण और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

मुख्य बिन्दु:

समुद्र मंथन मिशन

- **शुरुआत:** इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 2025 में भारत के नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन के रूप में की गई थी।
 - इसे मिशन मोड में लागू किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** इसका लक्ष्य तेल और गैस भंडार का पता लगाना है।

बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा संकट में कम मूल्य पर बिक्री को रोकने के लिए MIS के तहत आलू की खरीद को मंजूरी दी है।

मुख्य बिन्दु:

बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)

- **परिचय:** यह पीएम-आशा का घटक है। यह योजना जल्दी खराब होने वाली फसलों; जैसे टमाटर, प्याज और आलू के लिए है। इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य/मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत कवर नहीं किया जाता।
 - मूल रूप से MIS 1983 में शुरू की गई थी। बाद में, 2024 में इसे PM-AASHA में शामिल कर लिया गया।
- **कार्यान्वयन:** राज्यों के अनुरोध पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा।
- **उद्देश्य:** बंपर उत्पादन और कीमतों में गिरावट के दौरान कम-कीमत पर बिक्री को रोकना।
- **शर्तें:** यह योजना तब लागू की जाती है जब उत्पादन में 10% या उससे अधिक की वृद्धि होती है या फिर जब कीमतें पिछले सामान्य स्तर से 10% या उससे अधिक गिर जाती हैं।
- **हानि का साझाकरण:** केंद्र और राज्य 50:50 अनुपात में; पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 75:25 है।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक विनिमय (RELOS) समझौता

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित RELOS समझौता लागू हो गया।



मुख्य बिन्दु:

RELOS

- उद्देश्य:** यह सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई सुविधाओं के पारस्परिक उपयोग की अनुमति देता है। इसमें भारत के लिए आर्कटिक तक पहुंच भी शामिल है।
- दायरा:** इसमें लॉजिस्टिक्स सहायता, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय मिशन शामिल हैं।

Daily Current Affairs

Date : 21 April, 2026



- **उपयोग के प्रावधान:** इसमें 5 वर्षों के लिए एक-दूसरे के क्षेत्र में 3,000 सैनिकों, 5 युद्धपोतों और 10 विमानों की तैनाती का प्रावधान है।
- **महत्त्व:** यह वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच रक्षा सहयोग और समन्वय को मजबूत करता है। साथ ही, यह रूसी मूल के हथियारों के लिए निरंतर समर्थन भी सुनिश्चित करता है।



-:24:-

भारत-श्रीलंका संबंध: भारत के उपराष्ट्रपति की यात्रा

चर्चा में क्यों?

- भारत के उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग, आर्थिक सहायता और मछुआरों के मुद्दे पर चर्चा के साथ-साथ प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्ड से संबंधित नीति में बदलाव की घोषणा की।



मुख्य बिन्दु:

उपराष्ट्रपति की श्रीलंका यात्रा की मुख्य बातें

- ओसीआई एक्सटेंशन और डायस्पोरा एंगेजमेंट : पात्रता को भारतीय मूल के तमिलों की छठी पीढ़ी तक बढ़ाया गया है।
- प्रवासी समुदाय एक 'पुल' के रूप में: यह प्रवासी कूटनीति और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है, भारत में शिक्षा, रोजगार और गतिशीलता तक पहुँच को बढ़ाता है।
- कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक पहल: सीलोन एस्टेट वर्कर्स एजुकेशन ट्रस्ट के तहत समर्थन में वृद्धि, जिसका उद्देश्य भारतीय मूल के तमिलों की सामाजिक गतिशीलता में सुधार करना है।
- विकास सहयोग एवं समझौता ज्ञापन: चक्रवात दितवाह के बाद सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएँ ; और चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण (मुल्लैथीवू अस्पताल)।
- पड़ोसी-प्रथम नीति पर ध्यान केंद्रित: श्रीलंका ने आर्थिक संकट (2022) में भारत की भूमिका और आपदा राहत सहायता को स्वीकार किया।
- इससे हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होती है।

भारत-श्रीलंका संबंध

ऐतिहासिक विकास:

- प्राचीन और मध्यकालीन काल: साझा बौद्ध विरासत (श्रीलंका में अशोक के मिशन)। मजबूत सांस्कृतिक, भाषाई और व्यापारिक संबंध।
- औपनिवेशिक और स्वतंत्रताोत्तर चरण: ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय मूल के तमिलों का पलायन। नागरिकता संबंधी मुद्दे के समाधान के लिए सिरिमा-शास्त्री समझौता (1964) जैसे समझौते।

Daily Current Affairs

Date : 21 April, 2026



- **1980 के दशक के बाद का चरण:** श्रीलंका में जातीय संघर्ष और भारत की भागीदारी:
- भारत-श्रीलंका समझौता (1987)
- भारतीय शांति रक्षक बल (आईपीकेएफ) की तैनाती
- **21वीं सदी:** आर्थिक सहयोग, संपर्क और विकास साझेदारी की ओर बदलाव ।
- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में रणनीतिक महत्त्व में वृद्धि ।

संबंधों की वर्तमान स्थिति

- **राजनीतिक संबंध:** लगातार उच्च स्तरीय दौरे और संस्थागत संवाद।
- **आर्थिक संबंध:** द्विपक्षीय व्यापार, लगभग 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023-24); भारत श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों और निवेशकों में से एक है ।
- **विकास सहयोग:** भारत द्वारा 7 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता (ऋण और अनुदान)
- **कनेक्टिविटी :** फेरी सेवाएं, हवाई संपर्क, डिजिटल भुगतान (UPI), ऊर्जा कनेक्टिविटी।

-:27:-

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

भारत की पहली 'एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट'

🔊 चर्चा में क्यों?

- भुवनेश्वर में भारत की पहली 'एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट' की आधारशिला रखी गई।
- यह परियोजना घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रणाली को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह केंद्र एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड 'असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग' इकाई के रूप में कार्य करेगा।

📌 मुख्य बिन्दु:

घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता और महत्व:

- **आयात पर निर्भरता में कमी:** इससे घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमता सुदृढ़ होगी, जिससे आयात पर अधिक निर्भरता कम होगी।
 - वर्तमान में, भारत अपनी 90% से अधिक सेमीकंडक्टर आवश्यकताएँ आयात करता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला में विविधता:** वर्तमान में, विश्व के लगभग 70% सेमीकंडक्टर विनिर्माण दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में केंद्रित हैं।
- **उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा:** देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रणाली डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 5G/6G संचार, रक्षा, एयरोस्पेस और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के विकास में योगदान देगी।

Daily Current Affairs

Date : 21 April, 2026



- **आर्थिक सुरक्षा:** इससे कोविड-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संकटों के समय चिप की कमी जैसी स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी।
सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की शुरु की गई पहलें
- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) और सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम:** इनका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले की सुदृढ़ प्रणाली तैयार करना है, ताकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन के क्षेत्र में वैश्विक हब बन सके।
- **प्रतिभा और कौशल विकास:** इसमें 'चिप्स टू स्टार्टअप' (C2S) कार्यक्रम, AICTE पाठ्यक्रम अपडेट (विशेष इंजीनियरिंग कार्यक्रम शुरू किए गए) आदि शामिल हैं।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ:** माइक्रोप्रोसेसर विकास और 'डिजिटल इंडिया RISC-V' कार्यक्रमों के तहत शक्ति (SHAKTI), विक्रम (VIKRAM) और ध्रुव64 (DHRUV64) जैसे नेटिव (स्थानिक) प्रोसेसर बनाए गए हैं।
- **वैश्विक सहयोग:** उदाहरण के लिए, 'भारत-अमेरिका महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल (iCET)', अमेरिका के नेतृत्व वाली 'पैक्स सिलिका' (Pax Silica) पहल में शामिल होना, आदि।
- **राज्यों की नीतियाँ:** जैसे 'गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27'।
- **अन्य पहलें:** इलेक्ट्रॉनिक घटक और सेमीकंडक्टर विनिर्माण संवर्धन योजना (SPECS), इलेक्ट्रॉनिक्स घटक और विनिर्माण योजना (ECMS), आदि।

--:29:--